हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

2 RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:4 अंक:239 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, बुधवार, 03 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्रैक्टर पर बैठकर देखा आपदा का भयावह मंजर, किसानों की आंखों के आंसू

पथ प्रवाह, हरिद्वार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को लक्सर क्षेत्र में जलमग्न इलाकों के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ग्राउंड जीरो पर उमर गए। ट्रैक्टर पर बैठकर जलमग्न क्षेत्रों में पहुंचे। वोट के जरिए किसानों के खेतों की स्थिति को देखा। आपदा प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनने के साथ ही उनकी मदद करने का भरोसा दिया।

विदित हो कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के पर्वतीय इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से हरिद्वार के निचले इलाके लक्सर में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके है। खेत ?खलिहान जलमग्न है। किसानों की फसले पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सबसे पहले हरिद्वार जिले के लक्सर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचे। कठिन परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्रैक्टर पर बैठने का निर्णय किया और अपनी खुली आंखों से ग्रामीणों की समस्याओं को समझा और उनके दर्द को महसूस किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। हम हर संभव सहायता उपलब्ध कराएँगे और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने लक्सर हरिद्वार के गावों में जाकर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटे हुए पुल एवं जल से घिरे घरों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उनकी ज़रूरतों की जानकारी ली और आश्वस्त किया कि राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि- राहत शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था और उनमें समुचित भोजन, पानी, दवाइयाँ एवं साफ-सफाई की व्यवस्था हो। जिन परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसानों को फसल क्षति का त्वरित आंकलन कर मुआवजा प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के इस दौरे से स्थानीय जनता में एक सकारात्मक संदेश गया है और लोगों ने संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा दिखाई जा रही तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की।

इस अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा,जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी,उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रोहिला,पूर्व विधायक संजय गुप्ता,पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद,जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा, दायित्वधारी मंत्री श्यामवीर सैनी, जयपाल चौहान, ओमप्रकाश जमदग्नि, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल,अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एसपी देहात शेखर सुयाल, एस पी क्राइम जितेंद्र मेहरा,एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत एवं अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी व स्थानीय

सेमीकंडक्टर की हमारी यात्रा देरी से शुरू हुयी, लेकिन अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भले ही सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत की यात्रा देरी से शुरू हुई है, लेकिन अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती।

श्री मोदी ने यहां द्वारका स्थित यशोभूमि में तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। साल 2021 में सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत हुई थी और साल 2023 में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए मंजूरी प्रदान की गयी। साल 2024 में और संयंत्रों को मंजूरी दी गयी और साल 2025 में पांच और परियोजनाएं मंजूर की गयीं। कुल 10 परियोजनाओं में 18 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है।

उन्होंने कहा, भारत बैकएंड से निकलकर पूर्ण शक्तिशाली सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर बढ़ रहा है। भले हमारी यात्रा देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।

उन्होंने कहा कि टाटा और माइक्रोन ने टेस्ट चिप बनाने शुरू कर दिये हैं और पहला वाणिज्यिक चिप भी इसी साल बाजार में आ जायेगा।

प्रधानमंत्री ने घरेलू और विदेशी कंपनियों से इस क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार की नीति अल्पकालिक संकेत नहीं, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, आपकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया।

उन्होंने कहा कि दुनिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाली प्रतिभाओं में 20 प्रतिशत भारतीय है। देश के नवाचारों और स्टार्टअप कंपनियों से उन्होंने अपील की कि वे आगे आएं, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

किसानों, गामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दें बैंक:मुर्मु

चेन्नई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कि समय पर और किफायती ऋण प्रदान करके, वित्तीय साक्षरता प्रदान करके और कृषि-तकनीक पहलों को समर्थन देकर, बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मु यहां सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। 'स्वदेशी बैंकिंग की विरासत 120 वर्षों का उत्सव' शीर्षक के इस समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल एन आर रवि , केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमिलनाडु सरकार की समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री पी गीता जीवन उपस्थित थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि

जैसे-जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्टार्ट-अप से लेकर स्मार्ट सिटी तक, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई क्षेत्र) को विकास के इंजन में बदलने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारे बैंकों को वंचित और हाशिये पर पड़े वर्गों की मदद के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मसूरी गोलीकांड शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिवारजनों को किया सम्मानित

पथ प्रवाह, मसूरी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मसूरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने बेहतर भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 1994 का दिन राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जब मसूरी की वीरभूमि पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को मासिक पेंशन 3000 रुपये, घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये, तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। साथ ही, चिन्हित आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया गया है। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की है और युवाओं के लिए नकल विरोधी कानून लागू कर 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में सफलता दिलाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, अतिक्रमण मुक्त भूमि, दंगारोधी कानून और मदरसा बोर्ड सुधार के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, कानून और व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गढ़वाल सभा भवन निर्माण, सिफन कोर्ट मामला समाधान, मसूरी में वेंडर जोन स्थापना और अन्य मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरा स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की जन्मशताब्दी समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, दर्जाधारी सुभाष बड़थ्वाल, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन मल्ल सहित राज्य आंदोलनकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

एक नजर

पिथौरागढ़ में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है

कांग्रेस के पूर्व राज्य दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंगी द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और फिर जिलाधिकारी महोदय से मिलकर तुरंत राहत प्रदान करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा, जहां भी आपदा आई है, वहां प्रशासन द्वारा राहत राशि शीघ्र दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, जिनमें काली नदी और रामगंगा प्रमुख हैं। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी किनारे के इलाकों में खतरे की घंटी बज गई है। इसके अलावा, लगातार बारिश से खेत-खलिहानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। काली नदी और रामगंगा अपने पूर्ण उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है लगातार बारिश से खेत-खलिहानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री वितरित करने के लिए कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक - कर्मचारियों को राहत, विपक्ष में बौखलाहट

नवीन चौहान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों और जनता दोनों को बड़ी सौगात देकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी सरकार सिर्फ़ घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि ठोस फैसलों पर भरोसा करती है। कर्मचारियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्रीपुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (डीए) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 455 से बढ़ाकर 466 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 246 से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दिया गया है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे हजारों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। लेकिन पुष्कर

सिंह धामी यहीं नहीं रुके। उन्होंने विकास कार्यों को नई गति देने के लिए करोड़ों की योजनाओं पर मुहर लगा दी। पिथौरागढ़ जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के लिए 417.72 लाख और उपकारागार रुड़की में नए भवनों के लिए 251.49 लाख स्वीकृत किए गए हैं। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के किलातम में चैकडाम निर्माण हेतु ?95.49 लाख मंजूर किए गए हैं। वहीं, चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों व मेलास्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 81.50 लाख का बजट जारी किया गया है। इन फैसलों ने कर्मचारियों और जनता का मनोबल बढ़ाने के साथ ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल, विपक्ष जहां महंगाई और कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समय पर डीए बढ़ाकर विपक्ष की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संदेश साफ कर दिया है - ÷सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है। विकास और कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है। राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि धामी के इस मास्टर स्ट्रोक ने आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी गहरा असर डाल दिया है।

ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने तेल को और किया सस्ता, 'भारी छूट' से अमेरिका को लगेगी मिर्ची

मॉस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार भारत को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत ट्रंप की इन धमकियों को अनदेखा कर रूस से तेल खरीद जारी रखे हुए है। खबरों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी कच्चा तेल अब और सस्ता हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर 3-4 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। पिछले सप्ताह यह छूट 2.50 डॉलर थी, जबकि जुलाई में 1 डॉलर प्रति बैरल थी। सितंबर और अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर ये नई दरें लागू होंगी। ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह भारत पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया,

ताकि रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने के लिए भारत को सजा दी जा सके। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नई दिल्ली रूसी कच्चे तेल का प्रमुख आयातक बन गया है। वाशिंगटन की बार-बार आलोचना के बावजूद, भारत मॉस्को और बीजिंग के करीब आ रहा है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत और रूस के बीच विशेष संबंध हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों ने प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार बनने का वादा किया। वाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर पुतिन के हमले से पहले भारत रूसी तेल की खरीद तो दूर, बहुत कम मात्रा में तेल लेता था। अब रूस सस्ता तेल देता है, भारत उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में प्रीमियम पर बेचता है।

यह रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा देता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। उसने 2022 से रूस से कच्चे तेल की खरीद को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर लिया है।

अभाविप हरिद्वार की जिला समिति बैठक सम्पन्न, सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार पर हुई चर्चा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) हरिद्वार की जिला समिति की बैठक आज श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विशेष अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री श्री विपिन गुप्ता उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सदस्यता अभियान, इकाई गठन, विभाग अभ्यास वर्ग और राष्ट्रीय अधिवेशन शामिल थे। जिला प्रमुख राहुल सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है और आगामी समय में संगठन विस्तार पर विशेष बल दिया जाएगा। जिला सह संयोजक पायल प्रजापति ने बताया कि सदस्यता अभियान के माध्यम से हरिद्वार जिले में 15,000 से अधिक छात्र-छात्राओं को परिषद् से जोड़ा जाएगा और इकाई स्तर तक संगठन को सशक्त किया जाएगा। बैठक में प्रांत स्वास्थ्य कार्य प्रमुख डॉ. रितेश वशिष्ठ, विभाग संयोजक आर्यन नामदेव, विभाग संगठन मंत्री मनीष राय, नगर अध्यक्ष डॉ. हरदीप पांवरिया, मंत्री सूर्यांश, नितिन चौहान, योगिता, ईशा, सूर्यप्रताप राणा, वाशु सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी भूषण ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, बाहर से दवा मंगाने पर लगायी फटकार

स्वास्थ्य केंद्र में ही दवाई उपलब्ध करवाएं : ऋतु खण्डूरी भूषण

पथ प्रवाह संवाददाता/कोटद्वार 02 सितंबर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूरी भूषण ने मंगलवार को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के झंडीचौड़ और कलालघाटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जनता की समस्याओं को समझने के उद्देश्य से किया गया।

झंडीचौड़ स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं, साफ-सफाई और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की गहन जांच की। इस दौरान यह जानकारी मिलने पर कि चिकित्सक मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से दवाएं उपलब्ध कराने के बजाय बाहर की मेडिकल दुकानों से दवा लेने को कहते हैं, उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित डॉक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को आवश्यक दवाएं स्वास्थ्य केंद्र से ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

विधानसभा अध्यक्ष खण्डूरी ने कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की और अनुपस्थित कर्मचारियों के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को तत्काल फोन कर उनकी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कलालघाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां उपचार के लिए पहुंचे मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं।

उन्होंने बताया कि इस केंद्र में एचएससीएल (HSCL) द्वारा 32 बेड का अत्याधुनिक नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NIC) का निर्माण किया गया है, जो कोविड रिलीफ फंड से 3 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। यह इकाई शीघ्र ही आम जनता के लिए शुरू की जाएगी, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी ने कहा कि, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा कोटद्वार जैसे छोटे शहर में इतना अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराना सराहनीय कदम है, जो क्षेत्र की मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा।÷ इस अवसर पर कोटद्वार स्वास्थ्य प्रतिनिधि जितेंद्र नेगी, मंडल महामंत्री अभिषेक नेगी, रजत भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

श्री स्वामी भूमानन्द अस्पताल दूरदर्शी सोच और सेवा-भाव का सजीव उदाहरण: त्रिवेन्द्र

श्री स्वामी भूमानन्द अस्पताल के नव-निर्मित ओपीडी भवन और एमआरआई सेंटर का उद्घाटन

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, तीर्थनगरी हरिद्वार में स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी महाराज के 121वें प्रकट महोत्सव के अवसर पर श्री स्वामी भूमानन्द अस्पताल के विस्तार स्वरूप नव-निर्मित ओपीडी भवन और एमआरआई सेंटर का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज के छात्रों ने भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मंच को सजाया। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने छात्रों की प्रस्तुति की सराहना की और पूज्य महाराजश्री ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने

अपने संबोधन में हरिद्वार की पवित्रता और तीर्थनगरी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की कृपा और सानिध्य उनके जीवन में हमेशा प्रेरणास्रोत रहे हैं। इस अस्पताल के माध्यम से अब स्थानीय और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। सांसद हरिद्वार त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि यह अस्पताल महाराजश्री की दूरदर्शी सोच और सेवा-भाव का सजीव उदाहरण है। अब हरिद्वार और आसपास के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के मरीजों को दिल्ली या देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एमआरआई सेंटर जैसी आधुनिक सुविधा यहाँ उपलब्ध होना उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प की दिशा में यह प्रयास एक महत्वपूर्ण योगदान है।

अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एमआरआई सेंटर का उद्घाटन नवनीत सहगल, चेयरमैन प्रसार भारती ने किया। इससे न केवल हरिद्वार के बल्कि आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता वाली जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। अब मरीजों को देहरादून या दिल्ली जैसी दूरस्थ जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर ज्येष्ठ ट्रस्टी स्व. सेठ इन्द्रप्रकाश एवं स्व. निर्मला देवी के पुत्र सरेश कुमार गर्ग ने अपने माता-पिता की स्मृति में एक हॉल का निर्माण कर अस्पताल को समर्पित किया। पूज्य महाराजश्री और संस्था के सभी भक्तगण ने उनके इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टरों और सहयोगियों को सम्मानित किया गया और संस्था के प्रति उनके योगदान की सराहना की गई। बतादें महाराजश्री के अथक प्रयास से हरिद्वार में अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 400-बेड वाला अस्पताल सुचारु रूप से कार्यरत है। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य अतिथियों सहित सांसद, विधायक, मेयर, ट्रस्टीगण, चिकित्सक और छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

एक नजर

ज्वालापुर डबल मर्डर कांड में दो आरोपी दोषी, आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। ज्वालापुर के बहुचर्चित डबल मर्डर कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी एवं विशेष लोक अभियोजक धर्मेश कुमार ने बताया कि घटना 3 अक्टूबर 2015 की रात लगभग साढ़े नौ बजे की है। कड़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित उर्फ बंटी के साथ पैदल शास्त्री नगर मार्केट की ओर जा रहा था। तभी आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर अपने भाई चिन्नु मेहता, महेश मेहता, सचिन और अरुण पुत्र छत्रपाल के साथ खड़े थे। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पंकज और उसके दोस्तों को देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पंकज ने इसे टालने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने चाकू, खुखरी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल रोहित को इलाज के लिए जॉली ग्रांट हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना के समय कई लोग इकट्ठा हो गए थे। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पंकज के पिता नौरतू ने उसी रात ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों आशीष मेहता, महेश मेहता और अरुण के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान महेश मेहता की मृत्यु के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई, जबकि एक अन्य आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की गई। वादी पक्ष ने मुकदमे में तीस गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी आशीष मेहता और अरुण को हत्या, जानलेवा हमला और गाली-गलौज करने का दोषी पाया। न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना, जानलेवा हमला के लिए 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना, तथा गाली-गलौज के लिए एक माह की कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने किया बीज बैंक का निरीक्षण

पथ प्रवाह संवाददाता/हरिद्वार, 2 सितंबर। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने मंगलवार को जनपद के नारसन विकासखंड में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग से स्थापित बीज बैंक का निरीक्षण किया। यह बीज बैंक नारसन के मखदुमपुर में स्थित नारी शक्ति सीएलएफ में स्थापित है। निरीक्षण के दौरान, सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने बीज बैंक के प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सीएलएफ की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की और फसलों की उपज तथा बीजों की गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रमाणीकरण से बीजों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को बेहतर उपज मिलेगी। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए, सीडीओ ने जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना और खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संपादकीय

भारतीय ब्राह्मण और अमेरिकन ब्राह्मण के बीच तू-तू, मैं-मैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय उद्योगपति जिसमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी शामिल हैं के लिए कहा, कि इन्होंने रूस से तेल खरीद कर भारी मुनाफाखोरी की है। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को ब्राह्मण बताते हुए (अंबानी और अडानी) को मुनाफाखोर बताया है। नवारो ने कहा, रूस से तेल खरीद कर यूरोपीय देशों में बेचकर इन लोगों ने भारी मुनाफा कमाया है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूस ने भारत के माध्यम से तेल बेचकर युद्ध लड़ा है। तेल की कमाई से रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। रूस का तेल यूरोपीय देशों को बेचा जा रहा है, जिसका फायदा भारतीय ब्राह्मणो को हो रहा है। भारत की जनता को तेल के इस खेल में नुकसान उठाना पड़ रहा है। कच्चा तेल रूस से सस्ते मे खरीदकर भारत की आम जनता को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। आम भारतीय नागरिकों को महंगा पेट्रोल-डीजल खरीदना पड़ रहा है। भारतीय उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढी हुई कीमतों के कारण भारत के लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है। उन्होंने भारत के नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा था, कि भारत, रूस के लिए धुलाई मशीन बनाकर रूस के अपराधों को साफ करके उसे लड़ाई लड़ने में मदद कर रहा है। भारत और रूस के बीच एक ऐसा गठजोड़ बन गया है, जिसका नुकसान यूक्रेन के साथ-साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो के इस बयान की भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता, पवन खेड़ा ने कहा नवारो को इस तरह की विवादित टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्होंने नवारो के इस तरह के निराधार बयान की निंदा करते हुए आपत्ति जताई है। पीटर नवारो और पवन खेड़ा के बयान के बाद बयान पर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष कूद पड़ीं। उन्होंने कहा, अमेरिका और यूरोपीय देशों में अमीरों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया जाता है। ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय उद्योगपतियों को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। सारी दुनिया में अभिजात्य वर्ग के लिए अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मण शब्द का ही उपयोग किया जाता है। भारत में मनुस्मृति की बात होती है। मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अमीर और अभिजात्य वर्ग के लोगों को उनके ऐश्वर्या के कारण ब्राह्मण माना जाता है। इससे स्पष्ट हो गया है, ब्राह्मण एक ऐसा कुलीन वर्ग होता है। जो हमेशा से दुनिया के देशों में सर्वोच्च सम्मान के साथ बिठाया जाता है। ब्राह्मण ही आम लोगों पर धन संपदा के बल पर राज करता आया है। देश कोई भी हो, सभी जगह कुलीन वर्ग के धनी लोगों को ब्राह्मण ही माना जाता है। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण नहीं हैं। भारत की वर्ण व्यवस्था में वणिक समाज के होने के कारण भारत में इन्हें वैश्य माना जाता है। वैश्य को ब्राह्मण कह देने से भारत की वर्ण व्यवस्था पर अमेरिका का हमला माना जा सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीटर नवारो के बयान पर आपत्ति जताकर भारत की पुरातन संस्कृति की रक्षा की है? वहीं सागरिका घोष ने अंग्रेजी भाषा में अमीरों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपयोग पर अपनी राय व्यक्त करके भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का काम किया है। इस आपत्ति के बाद निश्चित रूप से अमेरिका को ब्राह्मण शब्द को लेकर भविष्य में सतर्कता बरतनी चाहिए। नवारो ने अभी जो बयान दिया है। उसके लिए भाजपा को उनसे माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। अमेरिका ऐसे अनाप-शनाप बयान देकर भारतीय संस्कृति पर जो सीधा-सीधा हमला कर रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

भारत का आर्थिक मंथन और विकास का अमृत

हरदीप एस. पुरी

भारतीय सभ्यता में अरसे से यह मान्यता रही है कि कामयाबी से पहले परीक्षा होती है। समुद्र मंथन, जहां मथने की प्रकिया से अमृत निकला था, इसी तरह हमारे आर्थिक मंथन ने भी हमेशा ही नवीनता का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष1991 के संकट से जहां उदारीकरण का जन्म हुआ; वहीं महामारी से डिजिटल उपयोग तेज हुआ। और आज, भारत को एक ÷मृत अर्थव्यवस्था÷ कहने वाले संशयवादियों के शोर-शराबे के बीच - तीव्र विकास, मजबूत बफर, और व्यापक अवसर - की एक तथ्यपरक कहानी उभर कर सामने आई है।

जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर जरा गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह वृद्धि दर पिछली पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है- सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग 7.7 प्रतिशत, निर्माण 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र लगभग 9.3 प्रतिशत बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाने तरीके से बताई गई तेजी नहीं है। यह बढ़ते उपभोग, मजबूत निवेश और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय व पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करने वाले लॉजिस्टिक्स संबंधी सुधारों से हासिल नतीजों का सबूत है।

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह तेजी के मामले में दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं क्रमशः अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है। वर्तमान गति से, हम इस दशक के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार-विनिमय के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है। स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है – सुधारों के मजबूत होने और नई क्षमताओं के सामने आने के साथ-साथ वैश्विक वृद्धि में हमारी हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचे। विभिन्न बाजारों और रेटिंग एजेंसियों ने हमारे इस अनुशासन को मान्यता दी है। एसएंडपी ग्लोबल ने मजबूत विकास, मौद्रिक विश्वसनीयता और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का हवाला देते हुए, 18 वर्षों में पहली बार भारत की 'सॉवरेन रेटिंग' को उन्नत किया है। इस अपग्रेड से उधार लेने की लागत कम होती है और निवेशक आधार का विस्तार होता है। यह ÷मृत अर्थव्यवस्था÷ की धारणा को भी झुठलाता है। जोखिम के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी रेटिंग के साथ अपना मत दिया है।

उतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर इस सबका लाभ किसे मिला है। वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच, 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। यह बदलाव उन बुनियादी सेवाओं - बैंक खाते, रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, नल का जल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण - की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पर निर्भर है जो गरीबों को विकल्प चुनने का अधिकार देता है। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र और उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच विकास का यह पैमाना बेहद खास है। विकास का भारत का यह मॉडल आम सहमति के निर्माण, प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को महत्व देता है। यह घोषणा के मामले में धीमा, क्रियान्वयन के मामले में तेज और निर्माण की दृष्टि से टिकाऊ है। जब आलोचक हमारी तुलना तेज भागने वाले सत्तावादियों से करते हैं, तो वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम मैराथन धावक की तर्ज पर लंबी दूरी तय करने वाली एक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इस तीव्र विकास में किस प्रकार सहायक की भूमिका निभा रही है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा तेलशोधक (रिफाइनर) और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। हमारी तेलशोधन (रिफाइनिंग) क्षमता 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है और इस दशक के अंत तक इसे 400 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट रोडमैप हमारे पास उपलब्ध है। भारत की ऊर्जा संबंधी मांग - जो 2047 तक दोगुनी होने का अनुमान है - बढ़ती वैश्विक मांग का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होगी, जिससे हमारी सफलता वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा को सुधार के साथ जोड़ने का रहा है। तेल की खोज का क्षेत्र 2021 में तलछटी घाटियों के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 16 प्रतिशत से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। तथाकथित 'निषिद्ध' (नो-गो) क्षेत्रों में 99 प्रतिशत की भारी कमी ने अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। गैस मूल्य निर्धारण से संबंधी नए सुधारों - जिनमें कीमतों को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी से जोड़ा गया है और गहरे पानी एवं नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम की पेशकश की गई है - ने निवेश को बढ़ावा दिया है।

हमारी ऊर्जा की कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन की ही नहीं, बल्कि बदलाव की भी कहानी है। वर्ष 2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत के बराबर हो गई है और किसानों को सीधे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। सतत के तहत 300 से ज़्यादा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2028 तक 5 प्रतिशत मिश्रण का है और तेल से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ जगहों में काफी शोरगुल हुआ है। आइए तथ्यों को इस शोरशराबे से अलग करके देखें। रूस की तेल पर ईरान या वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह जी7/ईयू मूल्य-सीमा प्रणाली के अंतर्गत है जिसे जानबूझकर राजस्व को सीमित रखते हुए तेल प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे पैकेजों के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हरेक दौर का पालन किया है। प्रत्येक लेनदेन में कानूनी लदान (शिपिंग) एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) किए गए चैनलों का उपयोग किया गया है। हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। हमने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।

कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूस के तेल के लिए एक ÷लौंड्रोमैट÷ बन गया है। इससे अधिक निराधार बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत इस संघर्ष से काफी पहले दशकों से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और हमारे रिफाइनर विश्व भर से इस प्रकार के क्रूड का एक समूह बनाते हैं। निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रखता है। वास्तव में, रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप ने भी भारतीय ईंधनों की ओर रुख किया। निर्यात की मात्रा और रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) मोटे तौर पर समान ही हैं। मुनाफे लेने का इसमें का कोई सवाल ही नहीं है।

यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में उछाल आने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक रूप से कदम उठाए। तेल से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक के नुकसान को सहन किया। सरकार ने केन्द्रीय और राज्य के करों में कटौती की और निर्यात से जुड़े नियमों ने यह अनिवार्य किया कि विदेशों में पेट्रोल और डीजल बेचने वाले रिफाइनर को घरेलू बाजार में कम से कम 50 प्रतिशत पेट्रोल और 30 प्रतिशत डीजल बेचना होगा।

इन उपायों ने, काफी राजकोषीय लागत पर, यह सुनिश्चित किया कि एक भी खुदरा दुकान खाली न रहे और परिणामस्वरूप भारतीय घरों के लिए कीमतें स्थिर रहीं। बड़ा सच यह है कि वैश्विक तेल का लगभग 10 प्रातशत आपूर्ति करने वाले दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े उत्पादक का कोई विकल्प ही नहीं है।

जो लोग उंगली उठा रहे हैं, वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के अपने सभ्यतागत मूल्यों के अनुरूप भारत द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने से 200 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के विनाशकारी झटके को रोका गया। यह वही मेड इन इंडिया है जो विश्व दृष्टिकोण के लिए भारत में आकार ले रही नई औद्योगिक क्रांति को आकार देता है।

पंजाब में बाढ़ आखिर क्यों - क्या प्रकृति रुष्ट है?

डॉ प्रियंका सौरभ

प्रकृति चेतावनी देती है, रुष्ट नहीं होती - असली वजह इंसानी लापरवाही और असंतुलित विकास

पंजाब में बाढ़ को केवल प्राकृतिक आपदा कहना सही नहीं होगा। नदियों का स्वरूप, असामान्य बारिश और जलवायु परिवर्तन तो कारण हैं ही, लेकिन असली दोषी अनियोजित निर्माण, अवैध खनन, ड्रेनेज की उपेक्षा और धान-प्रधान कृषि पद्धति भी है। प्रकृति चेतावनी देती है, रुष्ट नहीं होती। यदि हम नदियों को उनका मार्ग दें, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और फसल विविधिकरण अपनाएँ, तो बाढ़ की मार को कम किया जा सकता है। पंजाब को चाहिए कि वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकास की नई राह तय करे।

पंजाब, जिसे देश की अन्नदाता भूमि कहा जाता है, आज बाढ़ की विभीषिका से बार-बार जूझ रहा है। खेत जलमग्न हो जाते हैं, गाँव डूब जाते हैं, सड़कें और मकान ढह जाते हैं। हर बार यह सवाल उठता है कि आखिर पंजाब में बाढ़ क्यों आती है? क्या यह केवल प्रकृति की रुष्टता है या फिर इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी अपनी भूलें भी जिम्मेदार हैं? सच यह है कि प्रकृति कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, वह केवल अपने नियमों और संतुलन के आधार पर काम करती है। जब हम इंसान उसकी मर्यादाओं को लांघते हैं, तो परिणाम हमें बाढ़, सूखा, प्रदूषण और आपदा के रूप में भुगतने पड़ते हैं।

पंजाब की धरती पाँच नदियों की भूमि कहलाती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ने इस राज्य की पहचान बनाई। इनमें से अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और मानसून के मौसम में बर्फ़ पिघलने व वर्षा के कारण जलस्तर अचानक बढ़ा देती हैं। नदियों की धाराएँ तेज़ होती हैं और जब वे मैदानों में प्रवेश करती हैं तो पानी फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर जैसे बड़े बांध भले ही बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बने हों, लेकिन जब इनसे अचानक पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। यह प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ प्रबंधन की कमी को भी उजागर करता है।

पिछले कुछ वर्षों में मानसून का पैटर्न काफी बदल गया है। पहले जहाँ बरसात धीरे-धीरे और लंबे समय तक होती थी, अब अचानक भारी वर्षा कम समय में हो जाती है। इससे नदियों और नालों में पानी का दबाव तेजी से बढ़ता है और फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ना और ग्लोबल वार्मिंग इसका बड़ा कारण है। इससे हिमालयी ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। परिणामस्वरूप गर्मियों और बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर अनियंत्रित ढंग से बढ़ जाता है।

प्राकृतिक बाढ़ को विनाशकारी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इंसानी हस्तक्षेप की है। नदियों के किनारों और तलहटी में अंधाधुंध निर्माण कार्य हुए। गाँव और शहर नालों व पुरानी जलधाराओं पर बस गए। रेत और बजरी का अत्यधिक खनन नदियों की गहराई और धार बदल देता है। जब पानी का मार्ग रुकता है तो वह आसपास की बस्तियों में घुस आता है। पंजाब में ड्रेन और नहरों का जाल तो है लेकिन अधिकांश जगह इनकी सफाई व मरम्मत समय पर नहीं होती। नतीजतन बारिश का पानी निकलने की जगह वापस गाँव-शहरों में भर जाता है। इसके साथ ही धान जैसी फसलों ने भूजल का अत्यधिक दोहन किया। मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हुई और प्राकृतिक जलसंचयन तंत्र टूट गया।

पंजाब हरित क्रांति का केंद्र रहा। यहाँ गेहूँ और चावल की खेती ने देश को अन्न सुरक्षा दी, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। धान की फसल पानी की अत्यधिक मांग करती है। हर साल लाखों ट्यूबवेल से भूजल निकाला गया। इससे भूमिगत जलस्रोत तेजी से सूख गए। जब ऊपर से भारी बारिश या बाढ़ आई तो जमीन उसे सोख नहीं पाई और जलभराव की समस्या बढ़ गई। वनों की कटाई और हरित क्षेत्र के सिकुड़ने से भी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा। नदियों के किनारे पेड़ों की जड़ें पानी को रोकती और मिट्टी को बांधती थीं, लेकिन अब कटान तेज़ हो गया है।

पंजाब में बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक संकट भी है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसान कर्ज़ में डूब जाते हैं। ग्रामीण आबादी बेघर हो जाती है और पलायन के लिए मजबूर होती है। सड़कों, पुलों और बिजली के ढांचे को भारी क्षति पहुँचती है। बीमारियों का प्रकोप फैलता है, खासकर डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ। मानसिक आघात से समाज में असुरक्षा और हताशा की भावना पनपती है। वास्तव में प्रकृति का कोई भाव नहीं होता। वह केवल संतुलन चाहती है। जब हम उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तब वह चेतावनी के रूप में बाढ़, सूखा या आपदा के रूप में सामने आती है। इसलिए यह कहना कि प्रकृति नाराज़ है, सही नहीं है। सच तो यह है कि इंसान ने प्रकृति को नाराज़ करने लायक हालात पैदा कर दिए हैं।

समाधान स्पष्ट हैं। नदियों के किनारे बाढ़ क्षेत्र को चिन्हित कर वहाँ निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पुराने नालों और ड्रेनों की नियमित सफाई व चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए ताकि नदियाँ अपने प्राकृतिक स्वरूप में बह सकें। धान के स्थान पर मक्के, दालों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे पानी की खपत कम होगी और भूजल का स्तर सुधरेगा। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की उपस्थिति में केदारनाथ-हेमकुंड रोपवे परियोजना के लिए समझौता

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे विकास के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच समझौता हुआ।

समझौते के अनुसार, इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 प्रतिशत और राज्य सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी के तहत 90 प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड में पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में खर्च की जाएगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री अजय टम्टा और उत्तराखण्ड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने के साथ पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं के मार्ग खोलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी, 4100 करोड़) और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब (12.4 किमी, 2700 करोड़) की रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में रेल, सड़क और रोपवे कनेक्टिविटी तेजी से विकसित हो रही है। उन्होंने चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज-टनकपुर मार्ग, और अन्य परियोजनाओं का हवाला देते हुए कनेक्टिविटी सुधार में प्रगति का जिक्र किया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि यह दिन राज्य में रोपवे विकास की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इन रोपवे परियोजनाओं के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस समझौते से राज्य में पर्यटन विकास, स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समझौता समारोह में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, अपर सचिव विनय कुमार, सचिव दिलीप जावलकर, धीरज गर्ब्याल, युगल किशोर पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएचएलएमएल राजेश मलिक, वाइस प्रेजिडेंट प्रशांत जैन, अपर सचिव अभिषेक रोहिला और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

एसटीएफ ने बड़ी साइबर ठगी का किया पर्दाफाश, दिल्ली से गिरफ्तार हुआ आरोपी

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़े साइबर ठगी मामले में दिल्ली से आरोपी शादाब हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर और फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर IPO और ट्रेडिंग के नाम पर लगभग 7 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपये की ठगी की थी। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि प्रकरण अगस्त 2025 में देहरादून निवासी एक पीड़ित द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोपी ने पीड़ित को व्हाट्सएप पर इंडोनेशिया आधारित नंबर +6281319835997 से लिंक भेजा, जिसके माध्यम से पीड़ित को "M2- Wealth Secrets Exchange Group" में शामिल किया गया। ग्रुप एडमिन अज्ञात थे। शेयर मार्केट और निवेश के नाम पर पीड़ित को भारी मुनाफे का लालच देकर लगातार बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया गया।

पीड़ित ने 22 जुलाई से 20 अगस्त 2025 के बीच लगभग 7.39 करोड़ रुपये कुल 15 अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए। आरोपी ने Cantillon.App और "Disciple Team" ग्रुप का उपयोग करते हुए पीड़ित को निवेश करने को मजबूर किया। Cantillon Capital Management की अज्ञात महिला ने निजी संदेशों के माध्यम से निवेश के लिए निर्देश दिए। जब पीड़ित ने पैसे निकालने का प्रयास किया, तो उससे 3 करोड़ रुपये टैक्स के नाम पर मांगे गए। एसटीएफ ने बताया कि अपराध में फर्जी पहचान, अंतरराष्ट्रीय नंबर और तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। ठगों ने नकली SEBI प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए और मानसिक दबाव डालकर पीड़ित पर नियंत्रण बनाए रखा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी के बैंक खातों में केवल कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ और देश के विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ कुल 33 साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें से चार स्न्ढ्ढक्र की पुष्टि हुई है। अभियुक्त शादाब हुसैन, पुत्र वाहिद हुसैन, निवासी 78, परवाना नगर, थाना इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश को दिल्ली के जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तारी टीम में निरीक्षक आशीष गुसाई, उप निरीक्षक कुलदीप टम्टा, अपर उप निरीक्षक गोपाल सिंह, कांस्टेबल सुधीश खत्री और कांस्टेबल मोहित शामिल थे।

एक नजर

किराये के मकान में जिस्मफरोशी का धंधा, दो महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददाता/देहरादून, 02 सितंबर। अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किराये के मकान में चल रहे जिस्मफरोशी के अवैध धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से मकान के केयरटेकर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें दो महिलाएं शामिल हैं। इस धंधे का सरगना राजकुमार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिशें जारी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय सूचना मिली थी कि हरबर्टपुर के सोनिया बस्ती क्षेत्र में किराये के मकान से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (॥ञ्ज) और विकासनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार देर रात छापा मारा। पुलिस को मकान के अलग-अलग कमरों में दो पुरुष और दो महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिले। तलाशी के दौरान वहां से आपत्तिजनक सामग्री और नगदी भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोतवाली विकासनगर में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम जय नारायण शर्मा (मकान का केयरटेकर), निवासी उत्तरकाशी, हरि किशोर, निवासी विकासनगर और विक्की, निवासी हरबर्टपुर है। गिरफ्तार महिला गाजियाबाद और यमुनानगर हरियाणा की रहने वाली हैं। फरार आरोपी राजकुमार, निवासी बाल्मीकि कॉलोनी, विकासनगर पहले भी देह व्यापार के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मकान को राजकुमार ने किराये पर लेकर देह व्यापार का धंधा शुरू किया था। वह बाहर राज्यों से युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवाता था। ग्राहकों से फोन पर संपर्क कर उन्हें कमरे तक पहुंचाया जाता और पैसों की लेन-देन की जिम्मेदारी केयरटेकर जय नारायण के पास थी।

फर्जी फौजी बनकर जमीन का फर्जीवाड़ा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददाता। देहरादून, 02 सितंबर। थाना रानीपोखरी पुलिस ने जमीन के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा करते हुए एक 80 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लापता फौजी हुक्म सिंह के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। थाना रानीपोखरी में वादी राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मादसी गडूल की तहरीर पर 4 मार्च 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा संख्या 22/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि के अंतर्गत भूपेन्द्र सिंह, तिलक सिंह (दोनों निवासी धौलास, विकासनगर) व सुरेश (निवासी सहारनपुर) के खिलाफ पंजीकृत हुआ था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2007 में भूपेन्द्र सिंह ने अपने साथियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर लापता फौजी हुक्म सिंह के नाम पर जाली विक्रय विलेख तैयार किया था।

महिला आयोग ने देहरादून को असुरक्षित शहर बताने वाले सर्वे को किया खारिज

पथ प्रवाह संवाददाता।

देहरादून, 02 सितंबर। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने ÷पी वैल्यू एनालिटिक्स÷ द्वारा हाल ही में प्रकाशित ह्रञ्जक्रढ्ढ-2025 सर्वे को खारिज कर दिया है। इस सर्वे में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सर्वे न तो राष्ट्रीय महिला आयोग और न ही राज्य महिला आयोग द्वारा कराया गया और न ही किसी सरकारी संस्था से जुड़ा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि यह सर्वे अपराध आंकड़ों पर आधारित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत धारणा और सीमित सैम्पल पर आधारित है।

सर्वेक्षण में देश के 31 शहरों को शामिल किया गया था और यह CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews) एवं CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) पद्धति पर आधारित था। देहरादून की लगभग 9 लाख की महिला आबादी में से केवल 400 महिलाओं से टेलीफोनिक इंटरव्यू के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि इतनी छोटी संख्या को पूरे शहर की महिला सुरक्षा की वास्तविक स्थिति मानना उचित नहीं है।

सर्वे रिपोर्ट में महिला सुरक्षा एप्स के उपयोग को मात्र 4 प्रतिशत दर्शाया गया, जबकि वास्तविकता में देहरादून जिले में गौरा शक्ति एप में 1.25 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 16,649 केवल देहरादून जिले की हैं। इसके अतिरिक्त, डायल 112, उत्तराखंड पुलिस एप, सीएम हेल्पलाइन और पुलिस वेबसाइट के सिटीजन पोर्टल का महिलाओं द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण में पुलिस से जुड़े दो बिंदु - पुलिस पेट्रोलिंग और क्राइम रेट - भी तथ्यों से मेल नहीं खाते। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वाधिक सुरक्षित शहर कोहिमा का पुलिस पैट्रोलिंग स्कोर 11 प्रतिशत है, जबकि देहरादून का स्कोर 33 प्रतिशत है। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट में पूरे देश का स्कोर 7 प्रतिशत और देहरादून का 6 प्रतिशत बताया गया। हाई क्राइम रेट में देहरादून का स्कोर 18 प्रतिशत दिखाया गया, जो वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में डायल 112 पर 12,354 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से केवल 2,287 (18%) शिकायतें महिलाओं से संबंधित थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें घरेलू झगड़ों से जुड़ी थीं, और केवल 11 शिकायतें लैंगिक अपराध/छेड़खानी से संबंधित थीं। महिला अपराधों पर पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 13.33 मिनट है, जो सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। देहरादून में बाहरी राज्यों से लगभग 70,000 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें 43% छात्राएं हैं। शहर में कई विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, स्.ह्र.स्. बटन, पिंक बूथ, एकीकृत सीसीटीवी सिस्टम जैसी सुविधाएं सक्रिय हैं। शहर में कुल 14,000 सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हैं और सभी कैमरों की गूगल मैपिंग की जा चुकी है। इसके अलावा, पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के साथ पुरूष और महिला चीता टीमें निरंतर निगरानी रख रही हैं। महिला आयोग ने कहा कि सर्वेक्षण में शहर की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में नहीं रखा गया और सुरक्षा की धारणा आयु, जीवनशैली और अनुभव पर भी निर्भर करती है। नाइट लाइफ जैसी पैरामीटर को देहरादून पर लागू करना भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह एक शांत शहर है। आयोग ने स्पष्ट किया कि देहरादून शहर हमेशा से सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। शहर में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, केंद्रीय संस्थान और पर्यटन स्थल स्थित हैं, जहां देश-विदेश के छात्र और पर्यटक सुरक्षित वातावरण में रहकर अध्ययन और पर्यटन कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि नीति निर्माण और सार्वजनिक निर्णयों के लिए सर्वेक्षण की पद्धति, सैम्पलिंग, प्रश्नावली और सुरक्षा की परिभाषा में पारदर्शिता आवश्यक है। विदित हो कि देहरादून की सुरक्षा को लेकर निजी सर्वेक्षण की धारणा वास्तविकता पर आधारित नहीं है। महिला आयोग ने स्पष्ट किया कि यह सर्वेक्षण केवल अवधारणाओं पर आधारित है, जबकि पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के सभी मानकों को सुदृढ़ किया है।

नए मतदेय स्थलों के निर्धारण को लेकर उत्तरकाशी में हुई बैठक, जिलाधिकारी ने कहा- मतदाताओं की सुविधा सर्वोपरि

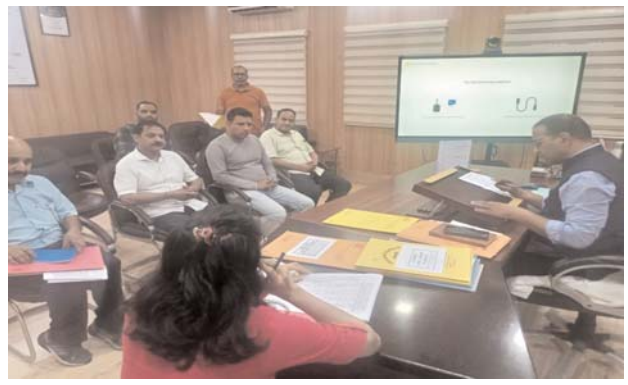

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए तहसील स्तर से प्राप्त नए मतदेय स्थलों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अपने सुझाव साझा किए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में पहले मतदान केंद्र तक पहुंचना कठिन था या जहां जनसंख्या वृद्धि के कारण मौजूदा केंद्रों पर अधिक दबाव पड़ रहा था, वहां नए मतदान केंद्रों की आवश्यकता महसूस की गई। तहसील स्तर से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की संख्या 1100 से अधिक है, वहां नए पोलिंग बूथ स्थापित करने के पांच प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से दो प्रस्ताव पुरोला विधानसभा क्षेत्र से और तीन प्रस्ताव यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। इसी तरह, जहां मतदाताओं को अपने केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, वहां भी नए मतदान केंद्रों की मांग उठी। इस श्रेणी में पुरोला से सात और यमुनोत्री से दो–कुल नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से मतदेय स्थलों के नाम परिवर्तन को लेकर एक प्रस्ताव भी मिला है। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को सभी प्राप्त प्रस्तावों को निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का अधिकार है कि उसे मतदान के लिए सहज और सुगम व्यवस्था मिले, और इसी उद्देश्य से नए प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। बैठक में अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश मोहन राणा, भाजपा से मनोज सिंह और मेघसिंह राणा, कांग्रेस से दिनेश गौड़ सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

बाल सम्प्रेक्षण गृह व वृद्धाश्रम का निरीक्षण, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला जज गुरुबख्श सिंह, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के निर्देश पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की ओर से बाल सम्प्रेक्षण गृह डुण्डा, वृद्धाश्रम डुण्डा, किशोर न्याय बोर्ड व विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी डुण्डा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी सचिन कुमार ने प्रभारी अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह डुण्डा से वार्ता करते हुए कहा कि यदि किसी विधि विवादित किशोर को निःशुल्क विधिक सहायता या अधिवक्ता की आवश्यकता हो, तो उसका प्रार्थना पत्र प्राधिकरण को भेजा जाए, ताकि संबंधित किशोर को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में गृह में एक विधि विवादित किशोर निरुद्ध है। वृद्धाश्रम डुण्डा के निरीक्षण में पाया गया कि यहां दो वरिष्ठ नागरिक निवासरत हैं। सचिव सचिन कुमार ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की खान-पान एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। निरीक्षण दल में सचिव के साथ प्रभारी अधीक्षक बाल सम्प्रेक्षण गृह डुण्डा, वरिष्ठ सहायक, चीफ लीगल एड डिफेंस कार्उसिल सिस्टम उत्तरकाशी व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य कमजोर वर्गों, विधि विवादित किशोरों एवं वरिष्ठ नागरिकों को न्याय व अधिकारों तक सरल पहुँच उपलब्ध कराना है।

उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित, स्याना चट्टी पुल पर खतरा बढ़ा

संवाददाता - सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जनपद में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जगह-जगह मलबा, पत्थर और पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने हालात को गंभीर मानते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें अलर्ट पर हैं, जबकि अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए श्रमिकों और मशीनरी तैनात की गई है।

सबसे गंभीर स्थिति यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास देखने को मिल रही है। यहां चट्टी वाला पुल लगातार बारिश और भूस्खलन के दबाव में है, जिससे पुल की मजबूती पर खतरा मंडराने लगा है। पुल के दोनों ओर मलबा जमने और पानी का तेज बहाव होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने पुल की सुरक्षा की निगरानी बढ़ा दी है और एनएच विभाग द्वारा तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास मलबा आने से बाधित है, हालांकि धरासू और नालूपानी के पास यातायात सुचारू बताया गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झर्जर गाड, जंगलचट्टी, बनास, नारदचट्टी, कल्याणी, हरेती, फेडी और विशेषकर स्याना चट्टी पुल के पास मलबा आने व भूस्खलन से बाधित है, जिसे खोलने के लिए एनएच विभाग द्वारा कार्य जारी है। बड़कोट-डामटा-विकासनगर, उत्तरकाशी-सुवाखोली-देहरादून और उत्तरकाशी-लम्बगांव मोटर मार्ग अभी तक सुचारू बताए गए हैं।

मौसम विभाग ने गंगोत्री, बड़कोट, पुरोला, जानकीचट्टी और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज गर्जना और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। हर्षिल-धराली में अतिवृष्टि के कारण आयी प्राकृतिक आपदा के बाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा जन जीवन को सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशों पर धराली में पर्याप्त मात्रा में राशन किट और रोजमर्रा का जरूरी सामान वितरित किया गया। साथ ही प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं।

एक नजर

वैष्णव ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए वैश्विक कंपनियों को किया आमंत्रित

नयी दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया की बड़ी कंपनियों से देश के सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश का आह्वान करते हुये मंगलवार को कहा कि भारत के विकास के साथ उनका भी विकास होगा।

दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का उत्पादन पिछले 11 साल में छह गुना और निर्यात आठ गुना अधिक हुआ है। ऐसे समय में जब दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल है, भारत रौशनी दिखा रहा है। यह पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की विकास दर में दिखता है।

उन्होंने सम्मेलन में आये दुनिया भर के उद्योगपतियों से कहा कि उन्हें भारत में निवेश करना चाहिये क्योंकि यहां की नीति में स्थिरता है, प्रतिभा का भंडार है, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत उत्पाद प्रधान अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत एक प्रगतिशील और मजबूत अर्थव्यवस्था है।

डॉ. मित्तल संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नये राजदूत नियुक्त

नयी दिल्ली 02 सितम्बर (वार्ता) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉ. दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि डा.मित्तल विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।

वह कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। डॉ. मित्तल श्री संजय सुधीर की जगह लेंगे जो अब तक संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत थे। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उन्होंने भारत और तालिबान शासन के बीच औपचारिक संपर्क शुरू कराने में अहम भूमिका निभायी थी।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच पिछले छह-सात वर्षों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के बाद इनमें नयी ऊर्जा आयी है। अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ-साथ वहां के कुछ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भी भारत की यात्रा की है।

कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी : भाजपा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाया।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं, जबकि कानून के मुताबिक देश के किसी भी नागरिक के पास सिर्फ एक वोटर आईडी होनी चाहिए। भंडारी ने कहा कि ऐसे में जब श्री खेड़ा का सच सामने आ चुका है तो क्या देश भर में घूमकर आम मतदाताओं के वोटों को फर्जी बताने और वोट चोरी का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी अपने पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे या कुछ बोलेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस मीडिया प्रमुख खेड़ा के पास दो वोटर आईडी .. एक्सएचसी 1992338 और एसजेई 0755967 हैं। यह दोनों वोटर कार्ड, दो अलग अलग विधानसभाओं के हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि तो क्या यह मान लें कि श्री गांधी के करीबी नेता वोट धांधली में संलिप्त हैं। वोट चोरी का सच अब सामने रख दिया गया है। भंडारी ने कहा कि श्री गांधी हर छह महीने में मुद्दे बदलकर देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, यह उनका पैटर्न भी है। श्री गांधी को देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए।

दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा

नयी दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह खतरे के निशान से करीब आधा मीटर ऊपर पहुंच गया निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज सुबह आठ बजे दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर दर्ज किया गया और यह लगाता बढ़ रहा है। यहां खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को हुई भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में यह स्थिति बनी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यमुनानगर जिला स्थित हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच दिल्ली में प्रशासन ने बचाव दल एवं अन्य संबंधित एजेंसियां को स्टैंड-बाय मोड में रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे यमुना किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। डूब क्षेत्र में और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को इन इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि यमुना में अब तक सबसे अधिक जलस्तर 208.66 मीटर रहा है जो 13 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था।

बुग्यालों की पुकार: कम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो - सीडीओ

पथ प्रवाह, संदीप बर्तवाल, चमोली

हिमालय की गोद में बसी हरी-भरी घास के मैदान, जिन्हें स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है, सिर्फ पर्यटन का आकर्षण ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जैवविविधता और जलवायु संतुलन के जीवनदाता भी हैं। इन धरोहरों को बचाने की मुहिम आज गोपेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से जोर पकड़ गई, जहाँ बुग्याल संरक्षण दिवस का आयोजन हुआ।

मैती समूह और बीएड विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. अमित कुमार जायसवाल ने की। उन्होंने वेदनी और पनार जैसे बुग्यालों का जिक्र करते हुए बताया कि ये केवल पर्यटन स्थलों की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी के आधार स्तंभ हैं।

विशिष्ट अतिथि राकेश गैरोला ने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाउस इफेक्ट और बदलती जलवायु पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि बुग्यालों का संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ किताबों और तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएगा।

मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी चमोली डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कहा–

बुग्यालों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। यह हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी की रीढ़ हैं। हमें इन्हें सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर मानकर बचाना होगा।

दूरभाष के माध्यम से जुड़े पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने भी बुग्याल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ सरकार या संस्थाओं का नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. एम.पी. नगवाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रकृति से जुड़कर इसे सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं।

सम्मान और सृजनात्मकता का संगम

कार्यक्रम में गिरी गंगा गौरव सम्मान 2025 की घोषणा भी की गई। इस सम्मान के लिए पत्रकार क्रांति भट्ट, लक्ष्मण सिंह नेगी, छायाकार हरीश भट्ट और पत्रकार ओमप्रकाश भट्ट का चयन हुआ।

साथ ही, बुग्याल संरक्षण विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सीनियर वर्ग में जसवंत प्रथम, सृष्टि द्वितीय और जयश्री तृतीय स्थान पर रहे। वहीं जूनियर वर्ग में जिज्ञासा प्रथम, आस्था द्वितीय और दिव्या तृतीय स्थान पर रहीं।

भविष्य की जिम्मेदारी

इस अवसर पर प्रो. चंद्रावती जोशी, डॉ. विधि ढौडियाल, डॉ. डी.एस. नेगी, डॉ. आर.के. यादव, डॉ. अखिलेश कुकरेती, डॉ. अखिल चमोली, डॉ. एस.एल. बटियाटा, डॉ. चंद्रेश जोगेला सहित अनेक शिक्षाविद और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की गूंज स्पष्ट है– हिमालय के बुग्याल सिर्फ हमारे आज की नहीं, बल्कि कल की भी जिम्मेदारी हैं। यदि हम इन्हें बचाएंगे, तभी ये आने वाली पीढ़ियों को हरियाली, शुद्ध जल और ताज़ी हवा की सौगात दे पाएंगे।

धारचूला में सुरंग से 11 कर्मी सुरक्षित निकाले गए, राहत कार्य जारी

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़ 7 2 सितंबर 2025

धारचूला के एलागाड़ स्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की सुरंग से राहत की बड़ी खबर आई है। लगातार कई घंटों से चल रहे ऑपरेशन के बाद हृष्ठक्रस्त्र और SDRF की टीमों ने सुरंग में फंसे 11 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी स्वयं मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। सुरंग के भीतर मौजूद कर्मियों को भोजन, पानी और मेडिकल सुविधा पहुंचाई गई है। 11 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अब 15 सदस्यीय दूसरी शिफ्ट को टनल में भेजा गया है। टनल गेट पर जमा मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर हटाने का काम तेज़ी से चल रहा है। वहीं, पिथौरागढ़ में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। काली नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और अन्य नदियों का प्रवाह भी तेज हो गया है। राहत दल ने साफ किया है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सुरंग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती।

गैरसैंण में जनसैलाब - प्रसूता और नवजात की मौत पर फूटा गुस्सा

सरकार–प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, न्यायिक जांच व डॉक्टरों की स्थाई तैनाती की मांग

पथ प्रवाह, गैरसैंण

गैरसैंण की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने आखिरकार लोगों का सब्र तोड़ दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिला और उसके नवजात की मौत से भड़के हजारों लोग मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। भारी बारिश के बावजूद रामलीला मैदान से शुरू हुआ सर्वदलीय आंदोलन तहसील और अस्पताल परिसर तक पहुंचा, जहां आक्रोशित जनता ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए।

आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें

- प्रसूता और नवजात की मौत की न्यायिक जांच।
- दोषी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
- महिला रोग, बाल रोग, हृदय रोग, फिजिशियन और सर्जन की स्थाई नियुक्ति।

- पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन बदलने और रेडियोलॉजिस्ट की स्थाई तैनाती।
- धरना, जुलूस और टकराव का माहौल

सुबह 10 बजे रामलीला मैदान से उठी भीड़ ने 11:30 बजे तहसील का रुख किया। यहां करीब डेढ़ घंटे तक नारेबाजी और धरना चलता रहा। इसी बीच लगभग 400 महिलाओं का दल सीधे अस्पताल पहुंचा और अस्पताल बंद करने की मांग पर अड़ गया। पुलिस व अधिकारियों की समझाइश भी बेअसर रही और आंदोलनकारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए।

प्रशासन हरकत में – न्यायिक जांच के आदेश

धरना स्थल पर एडीएम विवेक प्रकाश और सीएमओ अभिषेक गुप्ता पहुंचे। लंबी वार्ता के बाद जिलाधिकारी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। वहीं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और नई अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की मांग को स्वास्थ्य निदेशक तक पहुंचाया गया। रेडियोलॉजिस्ट की अस्थायी तैनाती दो दिन के लिए की गई है।

जनप्रतिनिधियों ने गरज कर साधा सरकार पर निशाना

नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि लंबे समय से मांगों को नज़रअंदाज करने का नतीजा है कि एक प्रसूता और नवजात को जान गंवानी पड़ी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरा सिंह फनियाल और सुरेश बिष्ट ने कहा कि सरकार गैरसैंण की स्वास्थ्य सेवाओं की जानबूझकर उपेक्षा कर रही है।

दो हजार से ज्यादा लोग हुए शामिल

गैरसैंण नगर क्षेत्र और आसपास के दर्जनों गांवों से करीब दो हजार लोग आंदोलन में शामिल हुए। महिला मंगल दलों की भारी भागीदारी रही। भीड़ ने साफ संदेश दिया - गैरसैंण की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं होगी।

एक नजर

सिलगड़ी का पल्ला चाला गीत में खेले खेल, सातू-आंठू महोत्सव के उत्साह को बरसात भी नहीं कर पाई कम

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित पारंपरिक सातू-आंठू महोत्सव में इस वर्ष भी महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश के बावजूद महिलाओं के उत्साह और सांस्कृतिक जोश में कोई कमी नहीं आई। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीतों की में खेल खेले, जिसमें उन्होंने सिलगड़ी का पल्ला चाला जैसे लोकगीतों पर थिरकते हुए पहाड़ी संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत की। रंग-बिरंगे परिधानों और लोक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से पूरा पिथौरागढ़ शहर गूंज उठा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, परंपराओं को बढ़ावा देना है और आने वाली पीढ़ी को लोकसंस्कृति से जोड़ने है। इस अवसर पर बच्चे, स्थानीय जनता, सांस्कृतिक संस्थाओं, और समाजसेवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

जिलाधिकारी ने घाट से पिथौरागढ़ दिल्ली बैंड एवं स्लाइड ज़ोनों का ग्राउंड जीरो पर किया निरीक्षण

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज हृ॥ 9 में दिल्ली बैंड और आसपास के स्लाइड ज़ोनों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पायर जियो कंपनी को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्रोन का उपयोग करते हुए मलबे के ऊपरी हिस्से की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु

जिलाधिकारी ने यूपीसीएल अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्लाइड ज़ोनों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे रात्रि में भी भूस्खलन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और कार्यों में तेजी लाई जा सके। यातायात एवं निगरानी व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि स्लाइड ज़ोनों के आसपास बैरियर लगाए जाएँ तथा पीआरडी, होमगार्ड

उत्तराखंड के पहाड़ों में क्यों नहीं लग पा रहे हैं उद्योग?

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की तस्वीर दो हिस्सों में बंटी नज़र आती है। एक तरफ हरे-भरे जंगल, बर्फ से ढकी चोटियाँ और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। दूसरी तरफ बेरोज़गारी, पलायन और वीरान गाँवों की सच्चाई है। हर चुनाव में नेताओं और अधिकारियों की जुबान पर यही वादे गूंजते हैं– ÷पर्वतीय जिलों का औद्योगिक विकास होगा।÷ लेकिन असलियत यह है कि पिछले 25 सालों से इन जिलों का औद्योगिक भविष्य केवल काग़ज़ों और फाइलों तक सीमित है।

सवाल यही है कि जब पहाड़ों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ उद्योग क्यों नहीं लग पा रहे? जवाब साफ है–यह असफलता प्रकृति की वजह से नहीं, बल्कि नीतिगत अंधेपन, अफसरशाही की सुस्ती, बैंकिंग तंत्र की हठधर्मिता और सरकार की खोखली घोषणाओं का नतीजा है।

पिथौरागढ़: सीमांत का अनदेखा खजाना

नेपाल और चीन की सीमा से लगा पिथौरागढ़ सामरिक और आर्थिक, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर्यटन, हर्बल इंडस्ट्री, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सीमा पार व्यापार की अपार संभावनाएँ हैं। लेकिन उद्योग विभाग की हालत यह है कि उसने कभी इस जिले को गंभीरता से देखा ही नहीं। सीमा क्षेत्र में हजारों सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन उनकी उपभोक्ता ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई स्थानीय उद्योग खड़ा नहीं किया गया। यहाँ न फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, न हर्बल रिसर्च सेंटर, न ही एडवेंचर टूरिज्म को उद्योग से जोड़ने की ईमानदार कोशिश। योजनाएँ फाइलों में बनती हैं, रिपोर्टें बनती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं उतरता।

चम्पावत: पलायन का सबसे बड़ा कारण

चम्पावत जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। कुटीर उद्योग, हर्बल प्रोसेसिंग सेंटर और इको-टूरिज्म के लिए यह ज़मीन आदर्श है। लेकिन सरकारी योजनाएँ केवल काग़ज़ी घोषणाओं तक सीमित हैं। सबसे बड़ी विडंबना बैंकिंग तंत्र है। स्थानीय युवाओं के स्वरोज़गार प्रस्तावों को ÷जोखिम भरा÷ मानकर खारिज कर दिया जाता है। बैंक ऋण देने से बचते हैं और अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने से। यही वजह है कि चम्पावत आज पलायन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। गाँव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, लेकिन उद्योग

विभाग और बैंक अधिकारियों की संवेदनाएँ अब भी कुंद हैं।

अल्मोड़ा- सांस्कृतिक राजधानी की उपेक्षा

अल्मोड़ा अपने हस्तशिल्प, पीतल शिल्प, अंगोरा ऊन और बुनाई कला के लिए विश्व में पहचान बना सकता था। लेकिन यहाँ शिल्पकार अपने हुनर को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद में हैं।

उद्योग विभाग और बैंकिंग व्यवस्था ने इन कलाकारों को हाशिये पर धकेल दिया। मेलों और प्रदर्शनियों में इनके काम को दिखाकर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, लेकिन उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार और ई-कॉमर्स नेटवर्क से जोड़ने का कोई स्थायी तंत्र नहीं बनाया गया। परिणाम यह है कि पीढ़ियों से चली आ रही कला लुप्त होने की कगार पर है।

बागेश्वर: कृषि उत्पाद, लेकिन प्रसंस्करण शून्य

बागेश्वर धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएँ भी हैं। मंडुवा, झंगोरा, आलू, राजमा, शहद और बुरांश जैसे उत्पादों से बड़े स्तर का प्रसंस्करण उद्योग खड़ा हो सकता था।

लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ न कोल्ड स्टोरेज है, न पैकेजिंग सेंटर और न ही निवेशकों को आकर्षित करने वाली कोई नीति। किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है। उद्योग विभाग केवल कार्यशालाएँ कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।

असली वजह: नीतिगत खामियाँ और बैंकिंग की जकड़न

उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियाँ आज भी मैदानी जिलों की सोच पर आधारित हैं। कर-छूट, बिजली सब्सिडी और भूमि सुविधाएँ मैदानी क्षेत्रों में बांट दी जाती हैं। पहाड़ों की समस्याएँ–भूस्खलन, परिवहन लागत, सीमावर्ती बाज़ार–कभी नीतियों में शामिल नहीं होतीं।

बैंकिंग तंत्र की मानसिकता और भी घातक है। बैंक अधिकारी मानते हैं कि पहाड़ों में उद्योग चल ही नहीं सकते। इसलिए लोन माँगने वाला युवा शाखा से निराश होकर लौटता है। कभी अपर्याप्त दस्तावेज़ का बहाना, कभी जोखिम का डर–नतीजा यह कि योजनाएँ मंचों पर घोषणा बनकर रह जाती हैं।

समाधान क्या है?

यह स्थिति बदली जा सकती है, बशर्ते सरकार और सिस्टम ईमानदारी से पहल करें-

1. विशेष औद्योगिक ज़ोन- सीमांत और पर्वतीय जिलों को विशेष उद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए।
2. बैंकिंग सुधार- स्थानीय युवाओं को आसान शर्तों पर ऋण मिले, गारंटी के लिए राज्य सरकार काउंटर गारंटी दे।
3. स्थानीय उत्पादों का नेटवर्क- मंडुवा, बुरांश, हस्तशिल्प, ऊन और हर्बल उत्पादों को ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ा जाए।
4. प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हब- हर जिले में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट अनिवार्य रूप से स्थापित हों।
5. अधिकारी जवाबदेही- केवल फाइल भेजने नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। पहाड़ों में उद्योग न लग पाने की वजह पहाड़ नहीं हैं, बल्कि सोच और प्रणाली है। यह असफलता उद्योग विभाग की निष्क्रियता, बैंकिंग तंत्र की जकड़न और नीतिगत अंधेपन का परिणाम है। यदि अब भी सरकार और सिस्टम ने आँखें नहीं खोलीं, तो आने वाले वर्षों में पहाड़ केवल पर्यटन पोस्टरों और वीरान गाँवों की तस्वीरों में रह जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया।

श्री मोदी ने इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये की राशि को हस्तांतरित किया। यह जीविका निधि साख सहकारी संघ पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जिससे माध्यम से सीधे और पारदर्शी ढंग से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा ।

इस जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धन उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत कलस्टर-स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि का योगदान करेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में उद्यमिता का विकास हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लघु उद्यमों और उत्पादक कंपनियों की स्थापना हुई है। ज्यादातर व्यवसायों में इन महिला उद्यमियों को 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की ऊंची ब्याज दरें वसूलने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस समस्या के निदान के लिए और उद्यमी महिलाओं की सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर निर्भरता कम करने और कम ब्याज दरों पर समय पर बड़ी ऋण राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जीविका निधि को एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में बनाया गया है।

यह प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम करेगी, जिससे जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे और तेजी से पारदर्शी धन हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट से लैस किया जा रहा है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मज़बूत करने और समुदाय-आधारित उद्यमों के विकास में तेज़ी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाओं ने इस कार्यक्रम को देखा।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज से तीन दिवसीय भारत यात्रा पर

नयी दिल्ली। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की आज से शुरू हो रही भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा को राजनयिक नजरिये से काफी अहम माना जा रहा है। श्री वोंग अपनी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शाम को यहां पहुंचेंगे।

दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह बुधवार को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कौशल विकास , डिजिटल सहयोग , विमानन , अंतरिक्ष और जहाजरानी क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है। श्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच भविष्य की भागीदारी को लेकर संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया जा सकता है। श्री मोदी के निमंत्रण पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान, श्री मोदी और श्री वोंग चार सितंबर को द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। वोंग का रसायन

एवं उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण; शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर; और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। श्री मोदी की सितंबर 2024 की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही श्री वोंग की यात्रा इस साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह यात्रा दोनों प्रधानमंत्रियों को दोनों पक्षों को मज़बूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा करने और भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्रदान करेगी। दोनों प्रधानमंत्री आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। उनकी इस यात्रा से आपसी संबंधों को साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने,उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी जैसे मौजूदा सहयोग के क्षेत्रों को और मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सीमा पार डेटा प्रवाह और बिजली व्यापार जैसे नए क्षेत्रों को भी सक्षम बनाया जा सकेगा और कौशल प्रशिक्षण के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम भी संभव होगा। पिछले माह नयी दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने स्थिरता, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी से संबंधित संभावित सहयोगों पर चर्चा की थी।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com